Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation respectively during the last three years vis-a-vis the complaints;

(c) whether Government propose to amend the rules, keeping in view the decisions given in favour of consumers and avoid litigations; and

(d) the total amount spent by LIC and GIC respectively in defending the claims field by the consumers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (d) The requisite information is being collected and shall be laid on the Table of the House.

Assistance by NABARD to Maharashtra

1923. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Maharashtra Government has requested for release of balance amount from NABARD under Maharashtra Agricultural and Rural Debt Relief Scheme;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) The details of the claims received by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and amounts sanctioned to banks in the State of Maharashtra under Maharashtra Agriculture and Rural Debt Relief (ARDR) Scheme are given below:

(Rs. in crores)

	Maharashtra State Cooperative Bank (SCB)	Maharashtra State Land Development Bank (SLDB)
Claims Lodged	377.56	111.38
Amount sanctioned	343.88	100.24
Balance of claims to be settled	33.68	11.14

NABARD have advised the Cooperative Banks to submit revised/final claims after excluding the relief provided by them to ineligibit borrowers. Release of the balance amount to banks would be considered by NABARD only after receipt of the same from the banks.

नई कपड़ा मिलों को ऋण

1924. **श्री गोविन्द राम आदिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा पूंजीनिवेश निगम उन नई कपड़ा मिलों और घाटे में चल रही मिलों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं हैं जो और अधिक आधुनिकीकरण करना चाहती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

(आई०डी०बी०आई०) ने सूचित किया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी०आई०) और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०) ने कपड़ा मिलों को नये एकक स्थापित करने और घाटा उठाने वाले रुग्ण एककों के पुनर्वास के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) द्वारा अनुमोदित राहत पैकेजों के अनुसार सहायता देना जारी रखा है। ये संस्थायें वर्तमान एककों के विस्तार और विविधीकरण के लिए वित्त सहायता भी प्रदान करती है।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में रुग्ण इकाइयों को दी गई सहायता

1925. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने उत्तर प्रदेश में रुग्ण-औद्योगिक इकाइयों को कोई सहायता प्रदान नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को यदि कोई सहायता दी गई है तो उसका जिला-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में रुग्ण एककों को मंजूर और संवितरित सावधि ऋण सहायता की प्रमात्रा निम्नलिखित है :—

(करोड़ रु०)

वर्ष	मंजूर		संवितरण	
	एककों की संख्या	राशि	एककों की संख्या	राशि
1991–92	2	3.98	9	5.62
1992–92	1	0.26	7	3.34
1993–94	2	4.37	2	0.65

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जिला-वार सहायता का ब्यौरा नहीं रखता है।

Japanese funds for Indian Projects under Official Development Assistance

1926. SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Japanese Government mission which held discussions with Indian Government recently have agreed to fund Indian Projects under Official Development Assistance (O.D.A.);

(b) if so, what are the projects to be funded under this scheme;

(c) whether the ongoing projects are also included in this scheme;

(d) what are those ongoing projects and financial involvement for each such projects; and

(e) what is the total amount to be funded under the scheme ?